प्रेस विज्ञप्ति

इरेडा के सीएमडी ने ग्रीन हाइड्रोजन लागत अंतर को पाटने के लिए अभिनव वित्तपोषण के लिए वकालत की

नई दिल्ली, 13 सितंबर 2024

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रदीप कुमार दास ने आज भारत मंडपम में आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन में "ग्रीन हाइड्रोजन के लिए वित्तपोषण: लागत अंतर को पाटना" के विषय के बारे में एक पैनल चर्चा में भाग लिया। ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को लागत-प्रतिस्पर्धी और बैंकेबल बनाने के लिए आवश्यकता पर जोर देते हुए, श्री दास ने अभिनव वित्तपोषण समाधानों के माध्यम से परियोजना लागत को कम करने के लिए इरेडा की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन को सौर, पवन और पनबिजली जैसी स्थापित अक्षय प्रौद्योगिकियों के अनुरूप शामिल किया गया।

इरेडा पहले से ही इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है, जिसने हाल ही में अपनी पहली ग्रीन अमोनिया परियोजना को वित्तपोषित किया है, जोकि ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में प्रवेश को चिह्नित करता है, इसके अलावा, इरेडा का लक्ष्य गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से निर्यात-उन्मुख डेवलपर्स के लिए विदेशी मुद्रा ऋण की सुविधा प्रदान करना है। ये ऋण डेवलपर्स को हेजिंग लागत पर 250-350 बेसिक पॉइंट बचाव करने के लिए मदद करेंगे, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन और संबंधित डेरिवेटिव वैश्विक बाजारों के लिए और अधिक आकर्षक बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने हाल ही में गिफ्ट सिटी में एक वित्तीय कंपनी के रूप में इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड (इरेडा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को अनंतिम पंजीकरण प्रदान किया है।

इरेडा द्वारा एक इन-हाउस, मानकीकृत क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल पर भी काम किया रहा है। यह मॉडल ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों को अधिक सटीक रूप से कैप्चर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और यह जोखिमों को ब्याज दरों में एकीकृत करता है। इस तरह के वित्तपोषण हस्तक्षेपों से परियोजना लागत में कमी आने और ग्रीन हाइड्रोजन उपक्रमों की समग्र बैंकिंग क्षमता में वृद्धि होने की भी उम्मीद है।

श्री दास ने एक ग्रीन हाइड्रोजन वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की चुनौतियों से निपटने के लिए समग्र समाधान योजनाएँ बनाने के महत्व के बारे में भी प्रकाश डाला। इसमें इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माताओं के लिए मजबूत परीक्षण सुविधाएँ विकसित करना, प्लांट डिज़ाइन का परीक्षण करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों की स्थापना करना और जोखिमों को कम करने और दीर्घकालिक परियोजना स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत ऑफटेक समझौतों को लागू करना शामिल है।

इस पैनल चर्चा में प्रतिष्ठित उद्योग के प्रमुखों और विशेषज्ञ भी शामिल थे, जिनमें आरईसी के सीएमडी,श्री वी के देवांगन, ओसीआईआर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री रंजीत गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के वरिष्ठ निवेश पेशेवर, श्री तरुण शंकर, ग्रीन हाइड्रोजन संगठन के इंडिया कंट्री मैनेजर, श्री निशांत बालशनमुगम, विश्व बैंक के इंडिया एनर्जी लीड, श्री मोएज चेरिफ, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के रणनीतिक पहल और नीति सलाहकार के वरिष्ठ प्रधान, श्री के मुकुंदन; और मॉडरेटर के रूप में केपीएमजी के पार्टनर, श्री हितेश सचदेवा शामिल थे।